



2026:AHC-LKO:41226-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 5721 / 2026

फैसल अली

.... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,

लखनऊ के माध्यम से और अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: अखिलेश पांडे, रजनीश तिवारी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 2

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. इस याचिका में उत्प्रेषण प्रकृति की एक रिट जारी करने की मांग की गई है, ताकि दिनांक 05.06.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट/वाद अपराध संख्या 298/2026, को अभिखण्डित किया जा सके। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74, 76, 115(2) के अंतर्गत चिनहट पुलिस स्टेशन, लखनऊ ज़िले में दर्ज की गई थी।

2. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अधिवक्ता और शिकायतकर्ता की ओर से वकालतनामा दाखिल करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार मिश्रा को सुना है और संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री को देखा है। शिकायतकर्ता की ओर से दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर ले लिया गया है। याचिकाकर्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों का लाभ पाने का हकदार है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के समान हैं।

3. राज्य के विद्वान अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि कथित अपराधों के लिए सात वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 जिसमें धारा 35(3) से 35(6) तक शामिल हैं, के अंतर्गत बताए गए ढंग और प्रक्रिया का पालन करेगी। ऐसी स्थिति में, जांच अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगा।

4. यह बताना उचित होगा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए जैसे ही प्रावधान पर ध्यान देते हुए, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 एससीसी 273** वाद में निम्नलिखित टिप्पणी की थी।

5. हमने राज्य के विद्वान अधिवक्ता के पक्ष पर विचार किया है। **अर्नेश कुमार के वाद (उपर्युक्त)** में निम्नलिखित (आवश्यक भाग) बात कही गई है:

"9. एक और प्रावधान, अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए, जिसका उद्देश्य अभियुक्त की आनावश्यक गिरफ्तारी या गिरफ्तारी के डर को रोकना है, उसे प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा जोड़ी गई धारा 41ए, जो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, इस प्रकार है:

"41ए. पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने का नोटिस -

(1) पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में, जहां धारा 41 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिसके विरुद्ध उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी मिली है, या उचित संदेह है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है, ताकि वह उसके सामने या नोटिस में बताई गई किसी अन्य स्थान पर पेश हो सके।

(2) जब किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह नोटिस की शर्तों का पालन करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(3) जब ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करता है और पालन करता रहता है, तो उसे नोटिस में बताए गए अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि पुलिस अधिकारी की राय में जिसके कारण दर्ज किए जाएंगे, उसे गिरफ्तार करना आवश्यक न हो।

(4) जब ऐसा व्यक्ति किसी भी समय नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने को तैयार नहीं होता है, तो पुलिस अधिकारी, इस संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन, उसे नोटिस में बताए गए अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है।"

"उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि उन सभी वादों में, जहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, पुलिस अधिकारी को अभियुक्त को एक निर्धारित स्थान और समय पर अपने सामने पेश होने का निर्देश देने वाला नोटिस जारी करना होगा। विधि ऐसे अभियुक्त को पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने के लिए बाध्य करता है और यह भी आवश्यक बनाता है कि यदि ऐसा अभियुक्त नोटिस की शर्तों का पालन करता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ पुलिस अधिकारी को लिखित कारणों के आधार पर यह लगता हो कि गिरफ्तारी आवश्यक है। इस स्तर पर भी, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा और मजिस्ट्रेट द्वारा उसी तरह इसकी जाँच की जाएगी जैसा कि पहले बताया गया है।

6. उपरोक्त बातों और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के बयान को ध्यान में रखते हुए जिसमें कहा गया है कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता के रुख को देखते हुए इस याचिका का निस्तारण किया जा सकता है और माननीय उच्चतम न्यायालय के **अर्नेश कुमार (उपर्युक्त)** वाद जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है और जिसका संबंधित भाग भी ऊपर दिया गया है में दिए गए निर्णय की टिप्पणियों को देखते हुए, इस याचिका का निस्तारण किया जाता है। साथ ही, पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से कार्रवाई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करें। इस धारा में गिरफ्तारी के लिए विधि, ढंग और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-ए के प्रावधानों के समान हैं, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अर्नेश कुमार (उपर्युक्त) वाद में स्पष्ट किया था।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

15 जून, 2026

केकेवी/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।